उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

विविध 4 (h) वाद संख्या–21/2020–21
(अंचल अधिकारी, चास बनाम् जलील अंसारी वगै0)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29/6/20	अभिलेख उपस्थापित। अनुमंडल पदाधिकारी, चास के माध्यम से अंचल अधिकारी, चास का विविध वाद संख्या–5542/2016–17 प्राप्त हुआ। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा राधानगर, थाना नं0–36/201, खाता नं0–154, प्लॉट नं0–220, रकवा–1.32 एकड़ भूमि, जिसका किस्म जंगल झाड़ी है, की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट संख्या 656 में चेतन मांझी का नाम दर्ज है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपने अभिलेख के आदेश फलक में वर्णित किया गया है कि मौजा राधानगर, थाना नं0–36/201, खाता नं0–154, प्लॉट नं0–220, रकवा–1.32 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है। (क) उक्त जमाबंदी दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम नहीं है। (ख) दिनांक 01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत नहीं है (ग) दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीद निर्गत नहीं है। (घ) वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वज के नाम अंकित नहीं है। (च) पंजी II में जमाबंदी सृजन का कोई आधार दर्ज नहीं है। (छ) दर्ज जमाबंदी में किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पंजी II के पृष्ट संख्या–656 पर जलील अंसारी वगै0 के नाम दर्ज जमाबंदी को अवैध मानते हुए भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, चास/ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के द्वारा संबंधित वाद में सूचना निर्गत कर सुनवाई करने का प्रयास किया गया, परन्तु सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी कभी भी उपस्थित नहीं हुए। अनुमंडल पदाधिकारी, चास /भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के द्वारा भी मौजा राधानगर, थाना नं0–36/201, खाता नं0–154, प्लॉट नं0–220, रकवा–1.32 एकड़ भूमि जिसका किस्म जंगल झाड़ी है, की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट संख्या 656 में चेतन मांझी के नाम दर्ज जामाबंदी को अवैध /संदेहात्मक मानते हुए भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द करने की अनुशंसा की गई है। इस न्यायालय के द्वारा प्रतिपक्षी का पक्ष जानने हेतु पुनः नोटिस निर्गत कर संबंधित वाद में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी लगातार अनुपस्थित रहे हैं।	

29/6

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके पास कोई ऐसी कागजात उपलब्ध नहीं है, जिससे उनके द्वारा दावा करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत कर सके। मौजा राधानगर, खाता नं0–136, खेसरा नं0–303, 220 और 230 का खतियानी रकवा 113.00 एकड़, 70.50 एकड़ एवं 77.00 एकड़ किस्म जंगल झाड़ी गत सर्वे खतियान में दर्ज है। वन विभाग के कब्जे में उक्त खेसरा नं0–230 में 10.80 एकड़ खेसरा नं–220 में 19.60 एकड़ कुल–30.40 एकड़ जमीन अधिसूचित है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के FRA की कार्रवाई एवं राजस्व विभाग की राज्यादेश सं0–2465/रा0, दिनांक 05.07.2019 के द्वारा कैबिनेट अनुमोदन के बाद शुल्क लेकर हस्तान्तरित की गयी। खेसरा नं0–303, 220, 230 में कुल 65.00 एकड़ एवं खाता संख्या 154 खेसरा 230, 220 में 0.75 एकड़ एवं 3.90 एकड़ जमीन हस्तान्तरित की गयी। इस प्रकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में विधिवत् शुल्क अदायगी के बाद 69.65 एकड़ जमीन हस्तान्तरित की गयी, जिसपर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का डिपो प्लान्ट एवं रेलवे ट्रेक का निर्माण कार्य हो रहा है, जो लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–202/95 टी गोदावर्मण थिरमूलपद बनाम् भारत सरकार वाद में पारित आदेश के अनुसार "जंगल, जंगल झाड़ी दर्ज भूमि चाहे वह किसी के स्वामित्व में हो वन भूमि मानी जाएगी।"

अंचल अधिकारी, चास/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास /अनुमंडल पदाधिकारी, चास द्वारा किये गये अनुशंसा एवं प्रतिपक्षी का लगातार अनुपस्थित रहने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर मौजा राधानगर, थाना नं0–36/201, खाता नं0–154, प्लॉट नं0–220, रकवा–1.32 एकड़, जिसका किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है, की पंजी II के पृष्ट संख्या 656 में जलील अंसारी वगै0 के नाम से चल रही जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार /झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉची के पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 6144/रा0, दिनांक 21.12.2017 द्वारा दिये गये निर्देश के तहत् रद्द की जाती है।

विषयगत रद्द की गई जमाबंदी की सम्पुष्टि सरकार से प्राप्त करने हेतु अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजें।

अपर समाहर्त्ता,
बोकारो।

उपायुक्त,
बोकारो।